DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER: नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शनिवार, 7 जनवरी 2023 ED----------

नारायणा: पार्क में गंदगी की भरमार, ट्रैक भी खस्ताहाल

नेबरहुड पार्क में उड़ती धूल-मिट्टी भी बिगाड़ रही सेहत

■ एनबीटी न्यूज, नारायणा

वेस्ट दिल्ली के नारायणा इलाके के नेबरहुड पार्क में गंदगी की भरमार है। पार्क के अंदर चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। ओपन जिम की मशीनें भी खराब पड़ी हैं। इसका इस्तेमाल करने पर चोटिल होने का खतरा बना रहता है।

नारायणा में रहने वाले देवेन्द्र तंवर ने बताया कि यह पार्क डीडीए की देखरेख में आता है और काफी बड़ा है। यह पार्क नारायणा विहार और नारायणा गांव के बीच में पड़ता है। नारायणा विहार और गांव की आबादी करीब 60 हजार है। बड़ी संख्या में लोग इस पार्क में सैर करने आते थे, लेकिन गंदगी के कारण अब लोगों ने पार्क में आना भी कम कर दिया है। स्थानीय निवासी जीवन तंवर ने बताया कि पार्क के किनारे गंदगी का ढेर लगा हुआ है। वहीं पार्क का जॉगिंग ट्रैक भी टूटा हुआ है, इस पर चलने में बुजुर्गों और बच्चों को दिक्कत होती है। वहीं आदित्य ने बताया कि देखरेख के अभाव में यह पार्क अब बदहाली का शिकार हो गया है। चारों तरफ फैली गंदगी से लोग परेशान हैं। हरियाली भी गायब होने लगी है, पार्क में धूल-मिट्टी उड़ती रहती है। इससे यहां आने वाले लोगों को दिक्कत होती है।

पार्क में लगी ओपन जिम की कई मशीनें भी अब खराब हो गई हैं

जगह-जगह दिख जाते हैं गंदगी के ढेर, वॉकिंग ट्रैक भी कई जगह से टूटा

रोड किनारे गंदगी

नरेला

डीडीए फ्लैट्स, सेक्टर बी2, नरेला रोड पर काफी दूर तक कूड़ा फैला हुआ है। गंदगी की वजह से लोगों को दिक्कत होती है।

- सिटिजन रिपोर्टर अर्जुन शर्मा

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER: दैनिक जागरण नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2023 DATED----------

जी-20 सम्मेलन से पूर्व राजधानी के फुटपाथ होंगे अतिक्रमण मुक्त

सुंदर व व्यवस्थित शहर बनाने को विशेष कार्ययोजना तैयार

G20 बैठक की तैयारियां

संजीव गुप्ता • नई दिल्ली

- पर्यावरण विभाग ने बनाई है 10 सूत्री विशेष कार्ययोजना, संबंधित विभागों को दिशा-निर्देश जारी
- जिन सड़कों के किनारे फुटपाथ नहीं होंगे, वहां धूल रोकने के लिए लगाए जाएंगे पेड़-पौधे

जी-20 सम्मेलन के मद्देनजर राजधानी को सुंदर और व्यवस्थित के साथ प्रदूषण मुक्त बनाने के प्रयास जारी हैं। इसी क्रम में पर्यावरण विभाग ने 10 सूत्री विशेष कार्ययोजना तैयार की है। इस पर क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों को मुख्य सचिव की ओर से दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

इस कार्ययोजना के तहत दिल्ली के सभी फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। जिन सड़कों के किनारे फुटपाथ नहीं होंगे, वहां मिट्टी न उड़े, इसके लिए पेड़-पौधे लगाए जाएंगे। सड़कों की साफ-सफाई के लिए 100 से अधिक मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें तैनात की जाएंगी। इसके अलावा पीयूसी प्रमाणपत्र की जांच के लिए दो शिफ्ट में विशेष अभियान चलाया जाएगा। निर्माण एवं ध्वस्तीकरण साइट पर धूल नियंत्रण के मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित होगा। 250 से अधिक एंटी स्मोग गन और पानी का छिड़काव करने के लिए टैंकर लगाए जाएंगे।

सभी 13 हाट स्पाट पर वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए हर जगह का अलग माइक्रो एक्शन प्लान बनाया जाएगा। कच्ची जमीन को सभी जगह पक्का किया जाएगा, ताकि धूल-मिट्टी नहीं उड़े। साथ ही 20 लाख पौधे लगाए जाएंगे और इस सबकी निगरानी के लिए एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाया जाएगा।

पहाड़गंज में अतिक्रमण कर लगे ठेले • जागरण आर्काइव

13 हाट स्पाट पर वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए बनाए जाएंगे माइक्रो एक्शन प्लान

100 से अधिक मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन तैनात की जाएंगी सड़कों की सफाई के लिए

250 से अधिक एंटी स्मोग गन और पानी का छिड़काव करने के लिए लगाए जाएंगे टैंकर

20 लाख पौधे लगाए जाएंगे, निगरानी के लिए एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनेगा

अमल के लिए मुख्य सचिव ने निकाला आदेश

इस कार्ययोजना पर बेहतर ढंग से अमल करने के लिए मुख्य सचिव ने सभी स्थानीय निकायों, सरकारी विभागों, पुलिस, निजी बिजली कंपनियों, डीडीए और एनबीसीसी सहित अन्य एजेंसियों को आपसी तालमेल के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इन सभी को एनजीटी, सीएक्यूएम, सीपीसीबी और डीपीसीसी के दिशा-निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है।

मंगलवार को होगी डीपीसीसी की बैठक

पिछले वर्ष जून में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की नई समिति बनने के बाद इसकी पहली बैठक मंगलवार 10 जनवरी की सुबह 10.45 पर बुलाई गई है। बैठक दिल्ली सचिवालय के तृतीय तल पर कान्फ्रेंस हाल में डीपीसीसी के नवनियुक्त अध्यक्ष अश्वनी कुमार की अध्यक्षता में होगी। इसमें डीपीसीसी के सदस्य सचिव डा. केएस जयचंद्रन के अलावा अन्य सभी सदस्य उपस्थित रहेंगे। हालांकि, बैठक का एजेंडा अभी तय नहीं हुआ है।

दैनिक जागरण
रविवार, 8 जनवरी, 2023

गाद को उठाना भूले कर्मचारी

पश्चिमी दिल्ली: द्वारका सेक्टर-12 स्थित आशीर्वाद चौक के पास मुख्य सड़क पर नालों के आसपास जमी मिट्टी व गाद को साफ कर निकासी का रास्ता सुगम हो गया है, पर सफाई के बाद डीडीए कर्मचारी उस गाद को उठाना भूल गए है। मुख्य सड़क पर थोड़ी-थोड़ी दूरी के अंतराल पर गाद के ढेर लगा हुआ है। (जासं)

उजाड़ पड़ा सेंट्रल वर्ज

पश्चिमी दिल्ली: पालम फ्लाईओवर के नीचे सेंट्रल वर्ज पर हरियाली के नाम पर कुछ एकाध पौधे ही नजर आते है। देखरेख के अभाव में यहां सभी पेड़-पौधे सुख गए है। कई बार शिकायत के बाद भी पीडब्ल्यूडी व डीडीए विभाग इस दिशा में सजग नहीं हो रहा है। आलम सेंट्रल वर्ज से काफी धूल-मिट्टी उड़ती है। यहां गंदगी का अड्डा बना हुआ है। लोगों ने कहा कि विभाग को चाहिए वह सेंट्रल वर्ज पर ऐसे पौधे लगाए, जिनमें ज्यादा पानी व धूप की जरूरत न हो। (जासं)

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NEW DELHI | SUNDAY, 8 JANUARY, 2023
NAME OF N ----------DATED----------

38 JNU, IIT-Delhi professors duped of crores by colleague

NEW DELHI: Several professors of JNU and other institutions have accused a former JNU employee of duping them of crores of rupees promising them homes on a DDA plot under a housing development scheme which was never there.

After waiting for over seven years, when these academics did not get anything except hollow promises, their patience ran out and they lodged a formal complaint with the Delhi Police.

Prima facie, police have found incriminating evidence against the accused in the matter and have lodged an FIR.

In 2015, just before he was due retirement, Dr DP Gaikwad, a technical staff in the Department of Environmental Science of JNU, floated a society and named it Noble Socio-Scientific Welfare Organization (NSSWO).

He sold its membership to his peers claiming that the society owned land in the L-Zone in Dwarka Najafgarh Area under the Land Pooling Policy.

He collected from Rs 2 lakh to Rs 16 lakh each from the academic and non-academic staff of JNU, IIT-Delhi, and other nearby institutions for three years in various installments, assuring them that the project was on.

"To make it appear real, he took several of us to show a piece of land, but later it turned out that NSSWO was not the owner of the land," Professor Gobardhan Das, Chairperson, Molecular Medicine, JNU, said.

"After collecting a hefty amount by cheating all the members, he stopped communicating and blocked all his phone numbers," Das, a victim of the scam, said.

After he went incommunicado, he was however traced in Gurugram by some professors who went there to confront him.

All the same, he again reeled them in with the offer of another lucrative scheme.

"He continued to play his trick of cheating and in February 2019, he offered to transfer our membership of NSSWO to another entity named Siddhartha Officers Housing and Social Welfare Society (SOHSWS) through which our flats were to be delivered, however, with a significantly escalated cost," Prof Biswajit Kundu from IIT-Delhi, one of the 10 complainants in the FIR, said.

"He didn't give any explanation for doing so, nor did he provide any details of any consequent changes in the agreement.

"In spite of repeated requests by several members, he never called a general body meeting of either society, nor took consent from the members of NSSWO for the changes made unilaterally," Kundu added.

Gaikwad himself admitted that there are 38 professors from JNU who have invested in the project, Das said.

"There are two from IIT and many more from other nearby institutions as far as I know. Initially, in a few cases, he returned 50 to 80 per cent money when he was forced to do so, but later he simply refused to return any money," Das added.

Dr Bindu Dey, a former senior scientist in the Department of Biotechnology in the Ministry of Science and Technology, was another victim of Gaikwad.

Having lost Rs 8 lakh in a bogus scheme, Dey in 2018 filed a complaint against Gaikwad at Vasant Kunj Police Station where an FIR was lodged against him. AGENCIES

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME O

pioneer

NEW DELHI I SUNDAY I JANUARY 8, 2023

38 JNU, IIT-D Profs fall prey to realtors' fraud

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

At least 38 professors of JNU and other institutions have accused a former JNU employee of duping them of crores of rupees promising them homes on a DDA plot under a housing development scheme which was never there.

After waiting for over seven years, when these academics did not get anything except hollow promises, their patience ran out and they lodged a formal complaint with the Delhi Police.

Prima facie, police have found incriminating evidence against the accused in the matter and have lodged an FIR.

In 2015, just before he was due to retiret, Dr DP Gaikwad, a technical staff in the Department of Environmental Science of JNU, floated a society and named it Noble Socio-Scientific Welfare Organisation (NSSWO).

He sold its membership to his peers claiming that the society owned land in the L-Zone in Dwarka Najafgarh Area under the Land Pooling Policy. He collected from ₹2 lakh to ₹16 lakh each from the academic and non-academic staff of JNU, IIT-Delhi, and other nearby institutions for three years in various installments, assuring them that the project was on.

Detailed report on P2

JNU Profs lose crore of rupees in real-estate fraud

Agencies: Several professors of JNU and other institutions have accused a former JNU employee of duping them of crores of rupees promising them homes on a DDA plot under a housing development scheme which was never there.

After waiting for over seven years, when these academics did not get anything except hollow promises, their patience ran out and they lodged a formal complaint with the Delhi Police. Prima facie, police have found incriminating evidence against the accused in the matter and have lodged an FIR. In 2015, just before he was due retirement, Dr DP Gaikwad, a technical staff in the Department of Environmental Science of JNU, floated a society and named it Noble Socio-Scientific Welfare Organisation (NSSWO).

He sold its membership to his peers claiming that the society owned land in the L-Zone in Dwarka Najafgarh Area under the Land Pooling Policy. He collected from Rs 2 lakh to Rs 16 lakh each from the academic and non-academic staff of JNU, IIT-Delhi, and other nearby institutions for three years in various installments, assuring them that the project was on.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE HINDU — Monday, January 9, 2023 DELHI — DATED

After eviction notice, Mehrauli JJ dwellers in the line of fire

Soibam Rocky Singh
NEW DELHI

Wheelchair user Aftab Alam has been living in the jhuggi at Mehrauli Archaeological Park for 30 years. SOIBAM ROCKY SINGH

In the jam-packed neighbourhood of south Delhi, the jhuggi jhopri (JJ), or slum, dwellers of Mehrauli Archaeological Park stare at an uncertain future after hundreds of them were served eviction notices by the Delhi Development Authority (DDA) on December 12, 2022.

The residents have been asked to vacate their homes, built on the government land. "We registered our houses here; many residents even sold theirs. These activities were allowed and in official knowledge; the staff responsible for these transactions should be taken to task first," rued Aash Mohammad Khan, a retired MCD safai karamchari, who has spent his life here.

"Where were the authorities when the houses and sheds were being built? How can they raze them now?" he said in a burst of emotions. "*Ghonsla ghonsla hota hai, chahe woh ameero ka ho ya garibo ka* (a nest is a nest, whether it belongs to the rich or the poor)."

Not new to litigations

Mehrauli Archaeological Park is one of the largest archaeological parks in the country, and comprises over 100 significant heritage structures and archaeological remains, monuments, graveyards and mosques.

Several litigations on removal of encroachments have been fought over the years to protect its heritage structures, ownership of certain plots of land and concerns of its existing inhabitants.

After the Indian National Trust for Art and Cultural Heritage had in July 2019 moved a petition, the Delhi High Court directed that the entire area under the park be secured and freed from encroachment. The court also cautioned that no construction activity shall be allowed in the area without its permission and every violation would be "viewed strictly".

After receiving the DDA's eviction notices, Mohammad Isreal and six other residents of the JJs moved the High Court, contending that they are daily wage workers living with their families and will be left homeless in the winter if the DDA was not restrained from carrying out the demolition.

They had argued that their houses cannot be demolished without rehabilitation as per provisions of the Delhi Slum & JJ Rehabilitation and Relocation Policy, 2015 of the Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB).

As per the terms of the policy, DUSIB is required to conduct a survey and workout a rehabilitation or relocation programme before carrying out the demolition, the JJ dwellers contended.

The High Court, however, declined Mr. Isreal's plea and instead gave him and the petitioners till January 15, 2023 to vacate their JJs.

Demarcation report

The DDA has defended its notices to the residents as compliance with the court's directions.

It has, however, assured the court that the removal of encroachments will not include religious structures and graveyards.

According to the agency, a 'Total Station Survey' was carried out on August 13, 2021, and the area of Mehrauli Archaeological Park demarcated.

The DDA has submitted that demolition would be done only as per the demarcation report prepared in 2021, and only encroachers removed.

However, Abdul Rehman, the caretaker of an old private Mughal-era graveyard in the area, said he supports the eviction drive. Pointing to a plot of land that holds half-a-dozen JJs, the 45-year-old said, "These houses have come up illegally."

Wheelchair user Aftab Alam has been living in the jhuggi adjacent to another private graveyard for the past 30 years. If evicted, he will have nowhere to go. The 35-year-old said, "Where will I go now?"